The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय) : अध्यक्ष महोदय, श्री अमित शाह जी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।?

? (व्यवधान)

SHRI HASNAIN MASOODI (ANANTNAG): Sir, I oppose the introduction of the Bill on the ground that the Jammu and Kashmir Reorganisation Act is a constitutionally suspect law. Judicial scrutiny is being done by the apex court. Even hearing has commenced. So, this is against the constitutional propriety and constitutional morality. You cannot amend an Act that is under judicial scrutiny and is a constitutionally suspect law. The constitutionality of Jammu and Kashmir Reorganisation Act is being examined by the Supreme Court and day-to-day hearing is scheduled to begin from 2nd August. It is better to stop the introduction of this Bill. I oppose the introduction on the ground that it is a constitutionally suspect law and the Constitution does not permit the introduction of the Bill. That is my objection to the introduction.

? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री नित्यानन्द राय : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

? (व्यवधान)

12.13 hrs